Maharashtra Model of Tribal Development

2849. SHRI ONKAR SINGH LAKHAWAT: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the States in which Maharashtra Model of tribal development has been adopted;

(b) what action is proposed against defaulter States; and

(c) whether Central Government propose to implement Maharashtra Model of the Planning Commission level i.e. earmarking of separate enhanced plan ceiling for Tribal Area Development?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) The States of H.P., Tripura, West Bengal, M.P., Gujarat & Kerala have adopted Maharashtra model since 1996-97. The Union Territory of A & N Island has decided to adopt the Maharashtra Model and modalities of the same are being worked out.

(b) No specific action is contemplated for those States that have not adopted the Maharashtra Model. Those States that have not adopted the Model are impressed upon in the Annual Tribal Sub Plan Meeting to do so.

(c) No Sir. There is no such proposal.

इस्पात का उत्पादन और मांग

2850. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात का उत्पादन इसकी मांग से अधिक है अथवा कम है या इसके विपरीत है और यदि हां, तो मांग तथा आपूर्ति में कितना अंतर है;

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान इस्पात के उत्पादन, मांग और इसकी खपत का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस्पात के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विगत में कोई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस्पात के निर्यात के लिए कोई बृहत योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह किस तारीख को प्रारम्भ की गई है और इस संबंध में भावी योजना क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) वर्ष 1997-98 के लिए परिसज्जित इस्पात (कार्बन) का उतपदन, मांग और अन्तर निम्नानुसार थे:-

(दस लाख टन)

मांग	उत्पादन	मांग/प्रत्यक्ष खपत
22.38	22.57	(+) 0.19

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और मांग/प्रत्यक्ष खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मात्रा: दस लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	मांग/प्रत्यक्ष खपत
1993-94	15.20	15.32
1994-95	17.82	18.66
1995-96	21.41	21.29
1996-97	22.72	22.12

(ग) इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात तथा संयुक्त संयंत्र समिति सेमीनार आयोजित कर रहे हैं। इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र जैसे नए क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए अनाज के लिए भण्डारण पात्र और पानी की टंकियों के लिए अच्छी बाजार सम्भावना सहित इस्पात के विशिष्ट उत्पाद अभिज्ञात किए गए हैं।

(घ) और (ङ) लोहे और इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में "इस्पात निर्यातक मंच" गठित किया है। प्रमुख इस्पात उत्पादक/एसोसिएशन इस मंच के सदस्य हैं।

सरकार ने निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करने का भी निर्णय लिया है।

निर्यात की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ अन्य उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

(1) बाजार विनिमय दर पर निर्यात आय का पूर्ण परिवर्तनीयता।

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को कच्चे माल की अपनी आवश्यकता को बिना शुल्क के आयात करने की सुविधा उपलब्ध कराना।

(3) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री के लिए दिया गया शुल्क वापिस करना।

(4) निर्यात से अर्जित आय को खंड 80 एच एच सी के अन्तर्गत आयकर से छूट देना; और

(5) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों पर ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) योजना के अन्तर्गत ड्यूटी क्रेडिट दरों में वृद्धि करना।

Setting up of Vijayanagar Steel Plant

2851. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the progress so far made with regard to the setting up of Vijayanagar steel plant in Karnataka; and

(b) the time by when the plant is likely to be set-up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) The Union Government had incorporated a new company viz. 'Vijayanagar Steel Limited' in December, 1982 to set up Vijayanagar steel plant. Land was acquired for the purpose. However, this did not materialise. Subsequently, Government of Karnataka entered into an Agreement with Jindal Iron & Steel Company Ltd. (JISCO) to set up an integrated steel plant. The State Government also signed an MOU with Mukund Ltd. for setting up of a steel plant. Both these plants were proposed on the same land.

As per available information, while no material progress has been made in the case of Mukund's steel plant, JISCO have formed a new company viz. Jindal Vijayanagar Steel Ltd. (JVSL) which has made substantial progress. JVSL has already commissioned its hot strip mill during June, 1997. Further, its first phase of iron and steel making facility is likely to be commissioned by August, 1998. The second phase is likely to be commissioned by March, 1999. The investment made in the project upto the end of May, 1998 is around Rs. 3250 crores.

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी

2852. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) कम्पनी द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही निर्माण परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ग) कम्पनी के वार्षिक लाभ और हानि की विगत पांच वर्षों की स्थिति क्या है; और

(घ) इस कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान न करने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) आज तक की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड